[2013] 16 एस.सी. आर. 910

सुनील महादेव जाधव

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1004 ऑफ 2007)

19 नवंबर, 2013

[ए. के. पटनायक और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 302, 342, 218, 193 सपठित धारा 34- अभिरक्षा में मृत्यु-पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाना -परिस्थितिजन्य साक्ष्य-निचली अदालत द्वारा बरी किया जाना- उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः गिरफ्तारी पंचनामा एवं गिरफ्तारी रजिस्टर पीडब्लू 21 और 22 को विधिवत प्रमाणित किया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे कूटरचित थे, अभियुक्त को धारा 218 और 193 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है- आरोपी को धारा 342 के तहत दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मृतक एक अपहरण कांड में सह अभियुक्त था- पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखे गए, जो मृत्यु का कारण था, गिरफ्तारी पंचनामा में वर्णन नहीं किया गया था- इसलिए, यह अनुमान लगाया

जाएगा कि वे चोटें मृतक को पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए लगी थीं-यह स्थापित किया जाता है कि मृतक पुलिस लॉक-अप में आरोपी नंबर 1 की हिरासत में अंतिम था-चोटों को साबित करने का भार आरोपी नंबर 1 पर था, जिसमे वह विफल रहा-इसलिए, अभियुक्त संख्या 1 को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा- मामले की परिस्थितियों ने स्थापित किया कि आरोपी नंबर 1 का इरादा मृत्यु कारित करने का नहीं था, उसे धारा 304 गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है-उसकी सजा धारा 304 से धारा 302 में बदल गई- इसलिए, उसकी सजा घटाकर सात साल कर दी गई और उस पर 3000 / रुपये का जुर्माना लगाया गया। चूंकि आरोपी संख्या 2 और 3 गिरफ्तारी के बाद जल्द ही पुलिस स्टेशन से चले गए। यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक उनके पास हिरासत में है-इसलिए, उन्हें मृतक पर घातक चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है-इसलिए, उनकी सजा को खारिज कर दिया गया-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 106.

अपीलकर्ता-अभियुक्त, पुलिस अधिकारी, पर एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक अपहरण के एक मामले में संदिग्ध था। उन्हें 16.12.1985 और 17.12.1985 की मध्यरात्रि में उनके घर से गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस हवालात में बंद कर दिया गया. दिनांक 17.12.1985 की सुबह मृतक मृत पाया गया। तीन अपीलकर्ता-अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा

342/34, 331/34, 326/34, 302/34, 218/34 एवं 193/34 के तहत मुकदमा चलाया गया। थाने के अन्य आठ पुलिस अधिकारियों पर भी आईपीसी की धारा 218 और 193 सपठित धारा 34 के तहत मुकदमा चलाया गया।

अभियुक्तों का बचाव यह था कि मृत व्यक्ति को उसके घर से नहीं, बल्कि चौक से उठाया गया था। गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करते समय, मृतक के शरीर पर कई चोटें देखी गईं और दर्ज की गईं और इसलिए, डी आरोपी व्यक्ति चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं थे।

निचली अदालत ने सभी आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्तों (अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3) को आईपीसी की धारा 302, 342, 218 और 193 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। अन्य आरोपियों के संबंध में बरी करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। इसलिए वर्तमान अपील आरोपी नंबर 1, 2 और 3 द्वारा पेश की गई।

आरोपी नंबर 2 और 3 द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए और आरोपी नंबर 1 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अपना अभिमत दिया की

अवधारणा: 1.1. वर्तमान मामले में, किसी चश्मदीद गवाह का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक को कैसे चोटें लगीं जिससे उसकी मृत्यु हुई

और इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन में अभियुक्त के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) सबूतों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि कोई उचित आधार न छूटे निष्कर्ष के लिए अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप होना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में, कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। [पैरा 20] [928-ई-एच; 929-ए]

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116: 1985 (1) धारा एससीआर 88- पर निर्भर था।

1.2. पहली परिस्थिति जिस पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया है वह यह है कि मृतक को वास्तव में 16.12.1985 की रात को अपीलकर्ताओं द्वारा उसके घर से उठाया गया था और जब उसे उठाया गया था तो उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसके घर से. इस परिस्थिति के प्रमाण के रूप में, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। उनके सबूत ठोस नहीं हैं. अधीनस्थ न्यायालय ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्यों पर अविश्वास किया और सही माना कि मृतक को एक चौक से उठाया गया था और जब उसे उठाया गया था तो उसके शरीर पर चोटें थीं। अपीलकर्ता, पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, जो गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) के साथ-साथ गिरफ्तारी पंचनामे (एक्सटी.76) की सामग्री और गिरफ्तारी रजिस्टर (प्रदर्श 76) में प्रविष्टि के गवाह थे। 134). चूँकि प्रदर्श 76 और प्रदर्श 134 की सामग्री पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 द्वारा साबित कर दी गई है और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रदर्श 76 और प्रदर्श 134 मनगढ़ंत हैं, अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 193 और 218 के तहत अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, मृतक अपहरण के एक मामले में अपने भाई के साथ सह-अभियुक्त था और उस मामले के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया था, अपीलकर्ताओं को भी आईपीसी

की धारा 342 के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता [पैरा 21] [929-सी-जी]

1.3. पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र (एक्सट.58) में जो चोटें देखी गई हैं और जो अंततः मृतक की मृत्यु का कारण बनीं, वे वैसी नहीं हैं जैसी गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में वर्णित हैं और जैसा कि पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22. द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार, प्रदर्श 76 में चोटों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के शरीर पर चोटों के कुछ लाल रंग के धब्बे और निशान थे और कहा जाता है कि यह चोट लगभग रात 10.30 बजे लगी थी। "16.12.1985 को तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा और चूँकि मृतक स्वयं उन चोटों के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चाहता था, चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं थीं। जब मृतक सुबह 7.05 बजे पुलिस स्टेशन के लॉक अप में मृत पाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो पीडब्लू-13 ने दिनांक 17.12.1985 को शाम 5.45-7.45 बजे के दौरान पोस्टमार्टम किया और मृतक के शरीर पर बाहरी चोटें देखीं। पीडब्लू-13 द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर पर देखी गई इन बाहरी चोटों में से कई का गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में वर्णन नहीं किया गया है। स्पष्ट निष्कर्ष यह होगा कि मृतक की गिरफ्तारी के बाद जैसा कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में दर्ज किया गया है, पुलिस स्टेशन में किसी ने मृतक के शरीर पर चोटें पहुंचाई हैं जिनका उल्लेख गिरफ्तारी पंचनामे में नहीं किया गया है। (प्रदर्श 76) [पैरा 22] [929-जी-एच; 930-ई-एफ; 932-सी-डी]

1.4. पुलिस स्टेशन की पुलिस स्टेशन डायरी में 17.12.1985 की प्रविष्टियाँ 108 से 120 तक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर (पीडब्लू-29) द्वारा ट्रायल कोर्ट में प्रदर्शित और साबित की गई हैं और प्रविष्टि सुबह 7.05 बजे की गई है। दिनांक 17.12.1985 को थाने की पुलिस स्टेशन डायरी में प्र.113 के रूप में अंकित किया गया। पुलिस/थाना डायरी के उद्धरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस मृतक को आरोपी नंबर 1 द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसे व्यक्तिगत रूप से रात में 00.45 बजे और सुबह 7.00 बजे पुलिस लॉक अप में रखा गया था, जब पुलिस कांस्टेबल नंबर 1276, 1672, 1627 को मृतक को प्राकृतिक कॉल और मुंह धोने के लिए बाहर लाने के लिए कहा गया तो मृतक नहीं उठा और उसका शरीर ठंडा हो गया था और उसकी सांसें बंद हो गई थीं और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार, पीडब्लू-29 के साक्ष्य के साथ पढ़ी गई धारा 113 स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि मृतक आखिरी बार 17.12.1985 की सुबह लगभग 00.45 बजे पुलिस लॉक-अप में आरोपी नंबर 1 की हिरासत में था और उसके बाद मृतक लॉक-अप में किसी की हिरासत में नहीं था. [पैरा 23] (932-ई-एफ; 933-ई-एफ; 934-सी)

1.5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। चूंकि यह आरोपी नंबर 1 था जिसने मृतक को दिनांक 17.12.1985 सुबह 00.45 बजे गिरफ्तार

किया था और उसकी गिरफ्तारी पूरी होने के बाद मृतक को पुलिस लॉकअप में रखा गया, यह आरोपी नंबर 1 पर था कि वह मृतक के शरीर पर चोटों के अलावा अन्य चोटों के बारे में बताए जो प्रदर्श 76 में देखी गई थीं। अभियुक्त नंबर 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है और न ही इन चोटों को समझाने के लिए बचाव में कोई सबूत पेश किया है। आरोपी नंबर 1 द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में या आरोपी नंबर 1 की ओर से पेश किए गए किसी भी सबूत के अभाव में, मृतक के शरीर पर इन चोटों पर स्पष्टीकरण के लिए इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि मृतक के शरीर पर ये चोटें आरोपी नंबर 1 और किसी और ने नहीं की हो. [पैरा 24] [934-डी-जी]

1.6. आरोपी नंबर 1 के खिलाफ साबित परिस्थितियों की श्रृंखला इस प्रकार है कि (i) उसने मृतक को 17.12.1985 की रात को गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श-76) के अनुसार सुबह 00.45 से 1.00 बजे के बीच गिरफ्तार किया था, (ii) चोटें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार पीडब्लू-13 द्वारा देखी गई चोटें गिरफ्तारी पंचनामे (प्रदर्श 76) में दर्ज चोटों से भिन्न और अधिक गंभीर हैं और (iii) गिरफ्तारी के समय दिनांक 17.12.1985 को प्रातः 0.45 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक के बीच मृतक की हिरासत किसी और के पास नहीं थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र परिकल्पना यह है कि यह आरोपी नंबर 1 है जो मृतक के शरीर पर उसकी

मृत्यु के समय चोटों के लिए जिम्मेदार है। [पैरा 25] [934-जी, एच; 935-ई-एफ]

1.7. आरोपी नंबर 1 के खिलाफ स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह नहीं दिखाते हैं कि आरोपी नंबर 1 का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था या उसका इरादा शारीरिक चोट पहुंचाने का था क्योंकि वह जानता था कि इससे मृतक की मौत होने की संभावना है या उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह भी स्थापित नहीं करते हैं कि वह जानता था कि मृतक के शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना है या उसकी मृत्यु होने की संभावना है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 300 में परिभाषित हत्या के अपराध की सामग्री आरोपी नंबर 1 के खिलाफ स्थापित नहीं की गई है। आरोपी नंबर 1 आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी नंबर 1 का मृतक की मौत का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था जिससे मौत होने की संभावना हो। मृतक के मामले में, आरोपी नंबर 1 को सात साल के कठोर कारावास की सजा देना और उस पर 3,000/- रुपये का जुर्माना लगाना और जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा देना पर्याप्त होगा। [पैरा 28] [937-डी-एच]

1.8. आरोपी नंबर 1 द्वारा दायर आपराधिक अपील में, आईपीसी की धारा 193, 218 और 342 के तहत आरोपी नंबर 1 की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध के बजाय धारा 302, आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है। [पैरा 30] [938-बी-सी]

2. हालाँकि, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि अभियुक्त संख्या 2 और 3 मृतक को चोट पहुँचाने के लिए जिम्मेदार थे जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। मृतक की गिरफ्तारी के समय और जब गिरफ्तारी पंचनामा (एक्सट.76) पुलिस स्टेशन में तैयार किया गया था, तब आरोपी नंबर 2 और 3 मौजूद थे और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि आरोपी नंबर 2 और 3 ने पुलिस छोड़ दी थी मृतक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद थाना मो. पुलिस स्टेशन की पुलिस स्टेशन डायरी (प्रदर्श 113) में प्रविष्टि में कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 ने मृतक को व्यक्तिगत रूप से लॉक-अप में रखा था। उक्त प्रविष्टि में हवालात में जहां मृतक को रखा गया था आरोपी नंबर 2 और 3 की उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । मुकदमे में यह सबूत होने के कारण, उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि मृतक की मृत्यु आरोपी नंबर 2 और 3 की हिरासत में हुई थी। आरोपी नंबर 2 और 3 की दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है। [पैरा 27] [936-डी-एच; 937-ए-सी]

राजस्थान राज्य बनाम काशी राम (2006) 12 एससीसी 254; 2006 (8) पूरक एससीआर 501 म.प्र. राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य (1995) 4 एससीसी 262: 1995 (1) पूरक एससीआर 44-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

2006 (8) पूरक। एससीआर 501 पैरा 19 को संदर्भित करता है

1995 (1) पूरक। एससीआर 44 पैरा 19 को संदर्भित करता है

1985 (1) एससीआर 88 पैरा 20 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1004/2007

आपराधिक अपील संख्या 1084/1988 और आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 82/1989 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2007 से।

आपराधिक अपील संख्या 1005 और 1067/2007.

आर. बसंत, उदय यू. ललित, सुशील करंजकर, के.एन. राय, अनीश आर. शाह, कार्तिक अशोक, बृज किशोर साह, शिवाजी एम. जाधव, संजय आर. हेगड़े, अतुल बी. दख, गौरव अग्रवाल, चिन्मय खलादकर, प्रेशित वी. सुरशे, संजय वी. खरदे, आशा गोपालन नायर उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए.के. पटनायक, जे.-

ये बंबई उच्च न्यायालय के 22.03.2007 के आम फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से तीन अपीलें हैं, जिसके द्वारा एक पुलिस उप-निरीक्षक और दो पुलिस कांस्टेबल को हटा दिया गया है। अरुण (इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित) की हिरासत में मौत का कारण बनने के लिए दोषी ठहराया गया।

मामले के तथ्य:

2. तथ्य संक्षेप में यह है कि उषा नाम की एक नाबालिग लड़की को चंद्रकांत से प्यार हो गया और उषा और चंद्रकांत दोनों कोल्हापुर से भाग गए जहां वे महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में कंकावली के पास उम्ब्राट में रहते थे। उषा के पिता मधुकर ने चंद्रकांत और मृतिका सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ उषा का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस उपनिरीक्षक सुभाष को मधुकर की शिकायत की जांच सौंपी गई, 16.12.1985 को मध्यरात्रि 12.00 से 12.30 बजे के बीच, सुभाष ने दो कांस्टेबलों, सुनील जाधव और आनंद भोंसले की मदद से, मृतक को, जो चंद्रकांत का बड़ा भाई था, गिरफ्तार कर लिया, इस संदेह पर कि उसने चंद्रकांत को कंकावली से उषा के साथ भागने में मदद की थी और मृतक को कोल्हापुर के शाहुपुरी पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में बंद कर दिया था।

दिनांक 17.12.1985 की सुबह लगभग 7.00 बजे शाहूपुरी पुलिस

स्टेशन के लॉक-अप में मृत पाया गया। मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम डॉ. विलास मनाडे और डॉ. बाबूराव घाटगे ने किया और मृतक के शरीर पर आंतरिक चोटों के अलावा कुल 19 चोटें पाई गईं। जांच की गई और सुभाष, आनंद भोंसले और सुनील जादव (इसके बाद क्रमशः आरोपी नंबर 1, 2 और 3 के रूप में संदर्भित) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी नंबर 1, 2 और 3 के खिलाफ धारा 342 के तहत आरोप लगाए गए। मृतक को गलत तरीके से कैद करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 34 के साथ पढ़ें, जानकारी हासिल करने के लिए मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 331 के साथ पढ़ें। चंद्रकांत के ठिकाने के संबंध में, मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 326 के तहत और मृतक की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत। आरोपी नंबर 1, 2 और 3 के अलावा, आठ अन्य आरोपी व्यक्ति थे जो शाहुपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी थे और सभी ग्यारह आरोपी व्यक्तियों पर शाहपुरी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड जालसाजी करने के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 218 सपठित धारा 34 और झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 193 सपठित 34 के तहत आरोप लगाया गया था।

3. मुकदमे में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक को 16.12.1985 की मध्यरात्रि में उसके घर से उठाया गया था और आरोपी

नंबर 1, 2 और 3 द्वारा शाहपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, और पीटा गया था और ताले में डाल दिया गया था। -पुलिस स्टेशन में और इस तरह की पिटाई से लगी चोटों के परिणामस्वरूप, मृतक की सुबह 5.00 बजे से 7.00 बजे के बीच लॉक-अप में मृत्यु हो गई। दूसरी ओर, बचाव पक्ष का मामला यह था कि मृतक को उसके घर से नहीं बल्कि सोन्या मारुति चौक से आरोपी नंबर 1, 2 और 3 द्वारा उठाया गया था और पुलिस जीप में शाहपुरी पुलिस स्टेशन लाया गया था। गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करने के समय, मृतक के शरीर पर कई चोटों को देखा गया और गिरफ्तारी पंचनामे में दर्ज किया गया और उसके बाद उसे शाहूपुरी पुलिस स्टेशन में लॉक-अप में डाल दिया गया और इसलिए आरोपी नंबर 1, 2 और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं थे।

4. विचारण न्यायालय ने अभियोजन की कहानी को खारिज कर दिया कि मृतक को उसके घर से उठाया गया था और माना गया कि उसे सोन्या मारुति चौक से उठाया गया था और शामराव दत्तात्रय पाटिल (पीडब्लू -19) द्वारा संचालित पुलिस जीप में शाहुपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और जब पीडब्लू-19 पुलिस स्टेशन के बहुत करीब खड़ी जीप में इंतजार कर रहा था, तो उसने पुलिस स्टेशन के अंदर पिटाई या रोने की कोई आवाज नहीं सुनी और इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी संख्या 1, 2 और 3 ने पिटाई की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से ही मृतक की बात गलत साबित होती है। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड

पर मौजूद मेडिकल सबूतों से यह भी पाया कि मृतक के शरीर पर चोटें भूरे रंग की थीं और 16.12.1985 और 17.12.1985 के बीच की रात को नहीं लगी हो सकती हैं। त्रय अदालत ने यह भी पाया कि मृतक के शरीर से दिनांक 02.08.1985 की एक मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श 71) बरामद की गई थी, जिससे यह स्थापित हुआ कि मृतक ने अपने रक्त और मूत्र की जांच कराई थी और तदनुसार ट्रायल कोर्ट ने माना कि ऐसा मानने का कारण था। मृतक को कोई बीमारी थी. ट्रायल कोर्ट ने आगे पाया कि 16.12.1985 और 17.12.1985 की मध्यरात्रि को मृतक की गिरफ्तारी के समय, एक पंचनामा (एक्सटेंशन 76) तैयार किया गया था, जिसमें गुंडू सातवेकर (पीडब्लू-21) और तानाजी जाधव (पीडब्लू) शामिल थे। -22) गवाह थे और इन दोनों गवाहों ने बयान दिया कि गिरफ्तारी पंचनामा के समय जब मृतक ने अपने कपड़े उतारे तो उसकी पीठ पर 2-3 खरोंच के निशान थे और कमर के हिस्से पर एक काला धब्बा था और जब आरोपी नंबर 1 मृतक से पूछा कि ये चोटें कैसे आईं, तो मृतक ने बताया कि जब वह कावला नाका से आ रहा था तो 2-3 लोगों ने उसे लात-घूंसों से पीटा था और तदनुसार पंचनामा (एक्सट.-76) तैयार किया गया था. इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 02.09.1988 के फैसले द्वारा आरोपी व्यक्तियों को आरोपी संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ धारा 302 सपठित धारा 34 तहत आरोप सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया।

5. व्यथित होकर, महाराष्ट्र राज्य ने सभी ग्यारह आरोपियों के खिलाफ आपराधिक अपील संख्या 1084 ऑफ 1988 दायर की और मृतक के भाई, शिकायतकर्ता बालासाहेब नामदेव पांडव ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 82 ऑफ 1989 दायर की। पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए आक्षेपित निर्णय में कहा कि मृतक को वास्तव में 16.12.1985 की रात को उसके घर से उठाया गया था और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जब उसे उठाया गया तो उसका शव था और आरोपियों के बचाव की यह कहानी कि मृतक को सोन्या मारुति चौक से उठाया गया था और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके शरीर पर चोटें थीं, झूठी थी और आरोपियों ने बचने के लिए यह कहानी गढ़ी थी। अपराधी दायित्व। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मृतक के शरीर पर पाई गई सभी चोटें मृतक को उसके घर से आरोपी नंबर 1, 2 और 3 द्वारा उठाए जाने के बाद लगी होंगी और इसलिए, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 342, 218 और 193 सपतिथ धारा 34 के तहत अपराध के दोषी हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 4 से 11 तक को सभी आरोपों से बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिससे व्यथित होकर अभियुक्त क्रमांक 1, 2 और 3 ने ये अपीलें दायर की हैं।

पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलें:

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष, विशेष लोक अभियोजक ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि आरोपी नंबर 1, 2 और 3 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। केवल यह तय करना आवश्यक था कि क्या मृतक की मृत्यु मानव वध से हुई थी और फिर भी उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या की सजा दर्ज की। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दोषी ठहराया है। उन्होंने आगे कहा कि सबूत के अभाव में कि कोई भी दस्तावेज़ आरोपी व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया था, उच्च न्यायालय ने शेष आठ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के तहत आरोप से बरी कर दिया, लेकिन गलती से अपीलकर्ताओं को धारा 218, भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषी ठहराया है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए किसी भी गवाह का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था कि अभियुक्त क्रमांक 1 से 3 ने गिरफ्तारी से पहले या बाद में मृतक को पीटा था और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कि आरोपी क्रमांक 1 से 3 ने मृतक को पीटा था। 1 से 3 तक मृतक के शरीर पर चोटें केवल परिस्थितिजन्य

साक्ष्य पर आधारित थीं। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में आरोपी नंबर 1 से 3 को दोषी ठहराने के लिए जो परिस्थितियां बनाईं, वे ये हैं कि

(i) मृतक को उसके घर से उठाया गया था दिनांक 16.12.1985 की रात को अभियुक्त क्रमांक 1 से 3 द्वारा;

(ii) जिस समय उसे हिरासत में लिया गया उस समय उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी;

(iii) गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) गलत तरीके से बनाया गया था ताकि यह प्रतीत हो सके कि मृतक को उसके घर के अलावा किसी अन्य स्थान से चोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था;

(iv) मृतक को अगली सुबह शाहूपुरी पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में मृत पाया गया:

(v) मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों से हुई (विस्तार 58) और

(vi) आरोपी संख्या 1 से 3 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत सबूत के अपने दायित्व का निर्वहन करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

8. उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने शरद बिरधीचंद सारडा बनाम. महाराष्ट्र राज्य, [(1984) 4 एससीसी 116] में पांच स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को साबित करने के पंचशील का निर्माण करते हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, ये पांच सुनहरे सिद्धांत इस मामले में संतोषजनक नहीं हैं, जिससे अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि पहला सुनहरा सिद्धांत यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और यहां तक कि यह सुनहरा सिद्धांत भी इस मामले में संतुष्ट नहीं है क्योंकि कोई भी परिस्थिति पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पहली परिस्थिति कि मृतक को उसके घर से उठाया गया था, पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए कि मृतक को आरोपी नंबर 1, 2 और 3 द्वारा उसके घर से उठाया गया था, उच्च न्यायालय ने मृतक के भाई पीडब्लू -5 की साक्ष्य पर भरोसा किया है, लेकिन पीडब्लू के साक्ष्य -5 ऐसा है, जिस पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। पीडब्लू-5 ने कहा है कि 16.12.1985 की रात को वह पहली बार दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनकर उठा और उसने देखा कि मृतक को पुलिस गैलरी से ले जा रही थी

और उसके बाद वह सो गये और नीचे जाना जरूरी नहीं समझा। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि पीडब्लू-5, जो मृतक का भाई था, यह देखने के बाद कि मृतक को पुलिस ले गई थी, मृतक को उठाने नीचे नहीं गया और पुलिस को देखने के बाद भी वह सोता रहा। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मृतक के एक अन्य भाई पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भी भरोसा किया है, जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि 17.12.1985 की सुबह लगभग 2.00 बजे, उसकी माँ ने उसे जगाया और बताया कि लगभग दो घंटे पहले मृतक को पुलिस शाहूपुरी पुलिस स्टेशन ले गई थी और उसके बाद वह शाहूपुरी पुलिस स्टेशन गया और अपने घर लौट आया और सो गया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-1 ने मृतक को पुलिस द्वारा ले जाते हुए नहीं देखा था और उसकी जानकारी का स्रोत उसकी माँ थी, लेकिन उसकी माँ से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष, कि मृतक को 16.12.1985 की रात को उसके घर से उठाया गया था, ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दूसरी परिस्थिति यह है कि मृतक के शरीर पर उसे हिरासत में लेने के समय कोई चोट नहीं थी। उन्होंने

निवेदन किया कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) जिस पर गवाह के रूप में पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, स्पष्ट रूप से बताता है कि मृतक को कुछ चोटें थीं जो मामूली थीं और महत्वपूर्ण नहीं थीं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने, हालांकि, माना है कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) एक गलत दस्तावेज है और यह दिखाने के लिए बनाया गया है कि मृतक को उसके घर के अलावा किसी अन्य स्थान पर गिरफ्तार किया गया था और उस समय उसे चोटें आई थीं। उन्होंने निवेदन किया कि मृतक को चंद्रकांत के साथ उषा के अपहरण के मामले में आरोपी बनाया गया था और आरोपी नंबर 1 को अपहरण के उपरोक्त मामले की जांच सौंपी गई थी और आरोपी नंबर 1 ने मृतक को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) की तैयारी किया और पुलिस स्टेशन के गिरफ्तारी रजिस्टर में उसकी गिरफ्तारी (प्रदर्श 134) के संबंध में प्रविष्टि भी की गई और मृतक की गिरफ्तारी के गवाह पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22, गुंडू सातवेकर और तानाजी जाधव थे। उन्होंने निवेदन किया कि पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 पुलिस कर्मी नहीं थे, बल्कि मृतक की गिरफ्तारी का गवाह बनने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाए गए स्वतंत्र गवाह थे और उनके साक्ष्य से पता चलता है कि जब मृतक ने पुलिस स्टेशन में अपने कपड़े उतारे थे, तो वे थे। उसकी पीठ पर 2-3 खरोंचें और कमर के हिस्से पर काला धब्बा था और जब आरोपी नंबर 1 ने मृतक से पूछा कि ये चोटें कैसे आईं, तो मृतक ने कहा कि जब वह कवला नाका से

आ रहा था तो उसे 2-3 लोगों ने पीटा था। चांड्या (चंद्रकांत) कहां है, यह पूछकर मुक्कों और लातों से मारा और उसके बाद आरोपी नंबर 1 ने उससे पूछा कि क्या वह डिस्पेंसरी जाना चाहेगा, लेकिन मृतक डिस्पेंसरी जाने की इच्छा नहीं रखता था क्योंकि चोटें मामूली थीं और तदनुसार पंचनामा तैयार किया गया और पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 ने पंचनामा पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने निवेदन किया कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) को पढ़ने से पता चलेगा कि पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 की साक्ष्य पूरी तरह से प्रदर्श 76 द्वारा पुष्ट हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह कि जब मृतक को गिरफ्तार किया गया था तो उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष भी था कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) गलत तरीके से बनाया गया था। यह दर्शाता है कि मृतक के शरीर पर आई चोटें अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत हैं।

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराने के लिए शेष तीन परिस्थितियाँ यह हैं कि मृतक 17.12.1985 को सुबह लॉक-अप में मृत पाया गया था और उनकी मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 58) में उल्लिखित चोटों से हुई, लेकिन यह स्थापित करने के लिए बिल्कुल भी सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को ये चोटें पहुंचाई थीं। बल्कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) से यह स्थापित हुआ कि मृतक के शरीर पर ये चोटें उसकी गिरफ्तारी से

पहले लगी थीं। उन्होंने निवेदन किया कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 58) में चोटों के विवरण में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि मृतक के शरीर पर चोटों का सावधानीपूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) तैयार करते समय आरोपी नंबर 1 द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, अपीलकर्ताओं को मृतक की हत्या करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर (पीडब्लू-13) जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 58) तैयार की है, की साक्ष्य से पता चलता है कि अन्य चोटों में चोट और सूजन भूरे या काले रंग के मलिनकिरण के साथ थी। उन्होंने निवेदन किया कि पीडब्लू-13 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि चोटों के भूरे रंग को देखते हुए, वे मृत्यु से दो से तीन दिन पहले की हो सकती हैं।

12. उन्होंने आगे निवेदन किया कि पीडब्लू-13 की साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक की टूटी हुई पसलियां डायाफ्राम और पेरिटोनियल गुहा, यकृत के फुफ्फुस में प्रवेश कर गई होंगी और इस प्रकार, यकृत को गहरी चोट पहुंची होगी और यह चोट लीवर के कारण लीवर में रक्तस्राव से हुआ होगा, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई होगी। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि वास्तव में यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि टूटी हुई पसलियों के कारण लीवर को चोट लग सकती है और इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि पसलियों को लगी चोटों के कारण मृतक के

लीवर को भी चोटें आई और परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पूछताछ के समय पंचनामा (प्रदर्श 71) मृतक की जेब में एक पैथोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध थी और इस पैथोलॉजी रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक एक पैथोलॉजी प्रयोगशाला में गया था और अपनी रक्त रिपोर्ट और मूत्र रिपोर्ट प्राप्त की थी। उन्होंने निवेदन किया कि इससे संकेत मिलता है कि मृतक किसी बीमारी से पीड़ित था और यदि जांच में यह पता लगाने के लिए निर्देशित किया जाता कि वह किस विशेष बीमारी से पीड़ित था, तो मृतक की मृत्यु का सही कारण सामने आ जाता।

13. अपीलकर्ता संख्या 1 (अभियुक्त संख्या 1) के विद्वान वकील श्री यूयू ललित ने जीप के चालक पीडब्लू-19 की साक्ष्य का हवाला दिया, जो पुलिस के एमटी अनुभाग से था। उन्होंने कहा कि पीडब्लू-19 एक स्वतंत्र गवाह था और उसके साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी नंबर 1 मृतक को रात में 12.40 बजे पुलिस स्टेशन लाया था और वह रात की ड्यूटी के लिए जीप में 1.10 बजे पुलिस स्टेशन से निकला था और सुबह 5.00 बजे पुलिस स्टेशन वापस आए और फिर 5.15 बजे अपने आवास के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यह पीडब्लू-19 का सबूत है की मृतक 16.12.1985 की रात 12.40 बजे के बीच आरोपी नंबर 1 की हिरासत में नहीं था, जब गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) दर्ज किया गया था और सुबह 7.00 बजे जब मृतक पुलिस लॉक-अप में मृत पाया गया था और

इसलिए, आरोपी नंबर 1 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत मृतक के आई चोटों के बारे में बताने के लिए नहीं कहा जा सका।

14. इसी प्रकार, अपीलकर्ता संख्या 2 (अभियुक्त संख्या 2) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बसंत आर. और अपीलकर्ता संख्या 3 (अभियुक्त संख्या 3) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वी. गिरी ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त मृतक को पुलिस स्टेशन लाए जाने के तुरंत बाद आरोपी नंबर 2 और 3 ने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया और यह पीडब्लू-23 (एक स्कूटर चालक) पीडब्लू-28 (मजिस्ट्रेट) और साहूपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक) पीडब्लू-29 की साक्ष्य से स्पष्ट होगा। उन्होंने आगे कहा कि मृतक कभी भी आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 3 की हिरासत में नहीं था और यह आरोपी नंबर 1 था जिसने मृतक को गिरफ्तार किया था और मृतक की गिरफ्तारी के लिए आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 3 को उसके साथ जाने का निर्देश दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक को पुलिस स्टेशन लाया गया और अधिकारियों को सौंप दिया गया, आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 3 ने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं दिखाया गया है . उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि मृतक आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 3 की हिरासत में नहीं था, इसलिए उन पर भारतीय

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत उन चोटों को समझाने का कोई बोझ नहीं डाला गया, जिनके कारण मृतक की मृत्यु हुई।

15. जवाब में, महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष तीन परिस्थितियों को स्थापित करने में सक्षम रहा है और ये तीन परिस्थितियाँ हैं (i) मृतक को 16.12.1985 की रात को आरोपी नंबर 1 से 3 द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनका घर जो कोल्हापुर के सोन्या मारुति चौक पर है; (ii) मृतक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था; और (iii) मृतक को 17.12.1985 की सुबह 7.05 बजे पुलिस हिरासत में मृत पाया गया और मौत एक अप्राकृतिक मौत थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये तीनों परिस्थितियाँ बिना किसी संदेह के साबित कर देंगी कि केवल आरोपी नंबर 1 से 3 ही थे जो मृतक की हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

16. पहली परिस्थिति को स्थापित करने के लिए कि मृतक को आरोपी नंबर 1 से 3 द्वारा उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, राज्य के विद्वान वकील ने न केवल पीडब्लू-1 से 5 के साक्ष्य पर बल्कि पीडब्लू -7 (नारायण) के साक्ष्य पर भी भरोसा किया जो मृतक के घर में काम कर रहा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में दिखाया गया है कि मृतक को सोन्या मारुति चौक से उठाया गया था और यह भी दिखाया गया था कि मृतक के शरीर पर काले और लाल चोट के

धब्बे और कुछ घर्षण के निशान थे, यह एक मनगढ़ंत दस्तावेज था और इसमें पुलिस स्टेशन डायरी (प्रदर्श 108 से 120) में प्रासंगिक समय पर मृतक की गिरफ्तारी की कोई संगत प्रविष्टि नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी रजिस्टर प्रविष्टि (प्रदर्श 134) भी एक मनगढ़ंत प्रविष्टि है क्योंकि गिरफ्तारी रजिस्टर में प्रविष्टियों के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रविष्टियाँ स्याही और लिखावट में हैं जो गिरफ़्तारी रजिस्टर की अन्य प्रविष्टियों की स्याही और लिखावट से भिन्न हैं।

17. राज्य के विद्वान वकील ने पीडब्लू-32 (जांच अधिकारी) के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब रात की ड्यूटी पर एक पुलिस अधिकारी वास्तविक काम के लिए वापस आता है, तो पुलिस स्टेशन डायरी में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्टेशन डायरी प्रविष्टि (प्रदर्श. 108) से पता चलता है कि रात में 00.10 बजे आरोपी नंबर 1 क्षेत्र में रात भर चेकिंग के लिए गया था और स्टेशन डायरी एंट्री (प्रदर्श 111) से पता चलता है कि सुबह 5.00 बजे आरोपी नंबर 1 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रात्रि दौर की जाँच से वापस आया और ये दो प्रविष्टियाँ (प्रदर्श 108 और 111) आरोपी नंबर 1 की लिखावट में हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार यह स्थापित करें कि आरोपी नंबर 1, 2 और 3 दिनांक 16.12.1985 की आधी रात से 17.12.1985 की सुबह तक घूम रहे थे और इस पूरी अवधि के दौरान मृतक आरोपी नंबर 1, 2 और 3 की हिरासत में था।

18. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 58) से मृतक के शरीर पर वास्तविक चोटों का पता चलता है और इनमें से कई चोटें गिरफ्तारी पंचनामे (प्रदर्श 76) या गिरफ्तारी रजिस्टर में (प्रदर्श 134) में परिलक्षित नहीं होती हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू-13 डॉ. विलास ने मृतक के शरीर पर देखी गई चोटों के बारे में बयान दिया है और उनके बयान से यह स्पष्ट होगा कि बाहरी चोटें संख्या 7, 12, 13 से 16 हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाए गए विवरण व्यापक थे और गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) या गिरफ्तारी रजिस्टर (प्रदर्श 134) में परिलक्षित नहीं हुए थे। उन्होंने डॉ. बाबूराव (पीडब्लू-20) के साक्ष्य पर भी भरोसा किया, जिन्होंने कहा है कि चोटें पोस्टमार्टम से 12 से 15 घंटे पहले लगी होंगी और यह भी कहा कि चोटें 17.12.1985 की सुबह 16.12 की रात के बीच लगी थीं।

19. राज्य के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत इन चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देने का भार अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 पर था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई और चूंकि आरोपी नंबर 1, 2 और 3 मृतक के शरीर पर लगी चोटों के बारे में बताने में सक्षम नहीं हैं, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं। इस निवेदन के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय राज्य बनाम काशी राम [(2006) 12 एससीसी 254]

पर भरोसा किया। उन्होंने इस कोर्ट के फैसले मप्र राज्य बनाम श्यामसुन्दर त्रिवेदी एवं अन्य [(1995) 4 एससीसी 262] का भी हवाला, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में, अगर अदालतों द्वारा जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया जाता है, तो न्याय की विफलता हो सकती है और इसलिए अदालतों को ऐसे मामलों को यथार्थवादी तरीके से और संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। वे इसके पात्र हैं, अन्यथा आम आदमी का न्यायपालिका से ही विश्वास उठ सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने का फैसला किया।

न्यायालय के निष्कर्ष

20. इस मामले में, किसी चश्मदीद गवाह का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक को कैसे चोटें लगीं जिससे उसकी मृत्यु हुई और इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया है। तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) में कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन में अभियुक्त के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित माना जा सकता है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

1. जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए;

2. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए;

3. परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

4. उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

5. साक्ष्यों की एक शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले से संबंधित इन पांच स्वर्णिम सिद्धांतों को इस मामले में साक्ष्यों का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखना होगा।

21. पहली परिस्थिति जिस पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया है वह यह है कि मृतक को वास्तव में अपीलकर्ताओं द्वारा 16.12.1985 की रात को उसके घर से उठाया गया था और जब वह था तो उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसके घर से उठाया गया. इस परिस्थिति के प्रमाण के रूप में, उच्च न्यायालय ने

पीडब्लू-1, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। हमने पीडब्लू-1, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्यों को ध्यान से देखा है और हमें उनकी साक्ष्य ठोस नहीं लगी। हमारी सुविचारित राय है कि ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्यों पर अविश्वास किया और सही माना कि मृतक को सोन्या मारुति चौक से उठाया गया था और उसके शरीर पर चोटें थीं। उसके शरीर को जब अपीलकर्ताओं ने पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए उठाया था, जो गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) के साथ-साथ गिरफ्तारी पंचनामे (प्रदर्श 76) और गिरफ्तारी रजिस्टर में प्रविष्टि (प्रदर्श 134) की सामग्री के गवाह थे। प्रदर्श 76 और प्रदर्श. 134 को पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 द्वारा सिद्ध किया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रदर्श 76 और प्रदर्श 134 मनगढ़ंत हैं, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 218 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि मृतक अपहरण के एक मामले में चंद्रकांत के साथ सह-आरोपी था और उस मामले के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

22. हालाँकि, हमने पाया है कि जो चोटें पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र (प्रदर्श 58) में देखी गई हैं और जो अंततः मृतक की मृत्यु का कारण बनीं, वे

वैसी नहीं हैं जैसी गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में वर्णित हैं जैसा कि पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 द्वारा दर्शाया गया है। गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में मृतक के शरीर पर चोटों के संबंध में यह कहा गया है:

"उनके शरीर का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि उनकी पीठ पर कुछ काले और लाल चोट के खेल देखे गए थे, साथ ही उनकी पीठ और कंधे पर घर्षण के निशान भी देखे गए थे। जब उससे पूछा गया कि ये चोटें कैसे लगीं, तो उसने कहा कि जब वह कवलनाका में था, तो रात करीब साढ़े दस बजे तीन अज्ञात लोगों ने उसे लात-घूंसों से नीचे गिराकर पीटा और उससे पूछा कि चंदू कहां है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह उन चोटों के लिए चिकित्सा उपचार कराना चाहते हैं, उन्होंने क्लिनिक में जाने से इनकार कर दिया। वह पुलिस से कोई शिकायत नहीं करना चाहता था. उक्त अपराध में उसे गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया तथा इसकी जानकारी दी गयी। यह पंचनामा हमारे कहे अनुसार हमारी उपस्थिति में 00.45 बजे शुरू किया गया और 01.00 बजे पूरा किया गया।

इस प्रकार, प्रदर्श 76 में चोटों के विवरण से प्रकट होता है कि मृतक के शरीर पर चोटों में कुछ लाल चोट के

धब्बे और निशान शामिल थे और कहा गया था कि 16.12.1985 को रात लगभग 10.30 बजे कवलनका में तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोट पहुंचाई गई थी और चूंकि मृतक खुद चिकित्सा उपचार नहीं चाहता था। उन चोटों के लिए, चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं थीं। जब मृतक सुबह 7.05 बजे पुलिस स्टेशन के लॉक अप में मृत पाया गया और उसे सीपीआर अस्पताल, कोल्हापुर ले जाया गया, पीडब्लू-13 ने 17.12.1985 को शाम 5.45 से 7.45 बजे के दौरान पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित बाहरी चोटें देखीं मृतक का शव:

1. दाहिने कंधे के शीर्ष पर भूरे रंग के मलिनकिरण के साथ 1" व्यास का गोलाकार घाव

2. चोट नंबर 1 के ठीक पीछे दाहिने कंधे पर घर्षण।

3. बाएं कंधे पर चोट, अंडाकार 2" x 1/2" भूरा मलिनकिरण।

4. चोट संख्या 3 के बाद बाएं कंधे पर कई छोटी खरोंचें।

5. बाईं कलाई पर भूरे रंग का मलिनकिरण के साथ संलयन, रेडियल पहलू गोलाकार 1" व्यास का।

6. कलाई के ऊपर बायीं बांह के रेडियल पहलू 2" पर मामूली घर्षण।

7. बाएं पैर के पृष्ठ भाग पर सूजन थी और उसका रंग भूरा-काला हो गया था, बाएं पैर के पृष्ठ भाग पर काले रंग का चीरा लगा हुआ था। टखने के मध्य भाग और पार्श्व भाग तक फैले पृष्ठ भाग पर चिह्नित हेमेटोमा था।

8. दाहिनी टिबिया के पतले हिस्से का संलयन, ऊर्ध्वाधर, माप 3":1" जो टखने के ऊपर से फैला हुआ है।

9. बायीं कोहनी पर चोट, पीछे का भाग अंडाकार 1" x 1/2" भूरा रंग का मलिनकिरण।

10. दाहिनी कोहनी पर चोट का चिकित्सीय पहलू 1" x 1/2"।

11. दाहिनी कोहनी पर चोट, पार्श्व पहलू 1" x 1/2"।

12. पीठ पर चोट का निशान, दाहिनी स्कैपुला के मध्य कोण से लेकर दाईं स्कैपुला के निचले कोण तक फैला हुआ, 6"x1' भूरे रंग का मलिनकिरण।

13. थ्रोसिक स्पाइन के ठीक दाहिनी ओर घाव का निशान टी1 से टी7 तक फैला हुआ, 7"x1" भूरा।

14. पीठ पर बायीं ओर क्षैतिज घाव का निशान, जो पीछे की सहायक रेखा से मध्य (रीढ़ की हड्डी) तक फैला हुआ है, 7"x1" भूरा।

15. वील मार्क तिरछा है जो बाएं स्कैपुला के निचले कोण से दाएं गुर्दे के कोण 6"x1" तक फैला हुआ है।

16. एल.4 के स्तर पर क्षैतिज वील मार्क लगभग 2"x1" भूरे रंग का मलिनकिरण मापता है।

17. दायें फलक कोण पर संलयन, गोलाकार 2" व्यास का भूरापन।

18. दाएं पार्श्विका क्षेत्र पर गोलाकार 1/2" व्यास का संलयन।

19. बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर 1/2" व्यास का गोलाकार संलयन।

पीडब्लू-13 द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर पर देखी गई इन बाहरी चोटों में से कई का गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) में वर्णन नहीं किया गया है। स्पष्ट निष्कर्ष यह होगा कि मृतक की गिरफ्तारी के बाद, जैसा कि गिरफ्तारी पंचनामे (प्रदर्श 76) में दर्ज है, साहूपुरी पुलिस स्टेशन में किसी ने मृतक के शरीर पर चोटें पहुंचाई हैं,

जिनका उल्लेख गिरफ्तारी पंचनामे (प्रदर्श 76) में नहीं किया गया है। 76).

23. अगला प्रश्न जो हमें तय करना है वह यह है कि मृतक की गिरफ्तारी के बाद वह कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने मृतक के शरीर पर चोटें पहुंचाईं। शाहपुरी पुलिस स्टेशन की पुलिस स्टेशन डायरी में 17.12.1985 की प्रविष्टियाँ संख्या 108 से 120 शाहपुरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर (पीडब्लू-29) द्वारा ट्रायल कोर्ट में प्रदर्शित और साबित की गई हैं और 17.12.1985 को सुबह 7.05 बजे की गई प्रविष्टि को साहूपुरी पुलिस स्टेशन की पुलिस स्टेशन डायरी में प्रदर्श 113 के रूप में चिह्नित किया गया है जो निम्नानुसार है:

"8. 07.05 Ex.113	Entry	इस समय, पुलिस निरीक्षक शाहपुरी को उनके निवास पर फोन नंबर 26013 पर टेलीफोन पर सूचित किया गया कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अरुण नामदेव पांडव उम्र 22 वर्ष निवासी 2643. सी-वार्ड शनिवारपेठ को गिरफ्तार किया है। चंबा गली. कोल्हापुर, जिसे पीएसआई पन्हाले द्वारा गिरफ्तार किया गया था और व्यक्तिगत रूप से रात में 00.45 बजे सीआर नंबर 321/1985 में पुलिस लॉकअप में रखा गया था। हमारे पुलिस

		स्टेशन में आईपीसी की धारा 365, 366 आर/डब्ल्यू 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब सुबह करीब 7 बजे पुलिस कांस्टेबल क्रमांक 1276, 1672, 1627 को लॉकर की चाबी देकर उसे नेचर कॉल और माउथवॉश के लिए बाहर लाने के लिए कहा गया, फिर उन्होंने बताया कि लॉक अप रूम में, उक्त अभियुक्त उठता नहीं है, उसका शरीर ठंडा हो गया है; तब मैं स्वयं हवालात कक्ष में जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं रुक गया और उसका शरीर ठंडा हो गया है और मुझे निश्चय हो गया है कि वह मर गया है, अत: आप तुरन्त आ जायें। फिर उन्होंने कहा कि वह आ रहे हैं, तदनुसार प्रवेश लिया जाता है।"

पुलिस स्टेशन डायरी के उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक अरुण नामदेव पांडव, जिसे आरोपी नंबर 1 द्वारा गिरफ्तार किया गया था, को व्यक्तिगत रूप से रात में 00.45 बजे और सुबह 7.00 बजे पुलिस लॉक अप में रखा गया था, जब पुलिस कांस्टेबल नं.1276, 1672, 1627 को मृतक को नेचर कॉल और मुंह धोने के लिए बाहर लाने

के लिए कहा गया था, मृतक नहीं उठा और उसका शरीर ठंडा हो गया था और उसकी सांसें बंद हो गई थीं और उसकी मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त प्रविष्टि प्रदर्श 113 पुलिस स्टेशन डायरी के संबंध में पीडब्लू-29 ने अपनी जिरह में भी यही कहा है।

7. दिनांक 17.12.1985 को सुबह 7.05 बजे मुझे थाना प्रभारी का फोन संदेश मिला कि पुलिस लॉक-अप रूम में आरोपी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने मुझे बताया कि उक्त आरोपी सीआर संख्या 321/85 में शामिल था, उसे सुबह 00.45 बजे गिरफ्तार किया गया और पुलिस लॉक-अप में रखा गया था। मैं सुबह 7.20 बजे पुलिस स्टेशन गया, पन्हाले भी मेरे आदेश के अनुसार पुलिस स्टेशन आया। मैंने स्टाफ सदस्यों से मौखिक रूप से उस आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी और मौत के बारे में पूछताछ की. रात को 0.45 बजे उस आरोपी को गिरफ्तार कर लॉकअप रूम में बंद करने के बाद मुझे रात को सूचना मिली. मुझे जानकारी मिली कि आरोपी 2 और 3 साइकिल से थाने से निकले थे और उस समय भी वे थाने नहीं लौटे थे.

इस प्रकार, प्रदर्श 113 के साथ पढ़ी गई पीडब्लू-29 की साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि मृतक आखिरी बार 17.12.1985 की सुबह 00.45 बजे पुलिस लॉक-अप में आरोपी नंबर 1 की हिरासत में था और उसके बाद मृतक किसी की हिरासत में लॉक-अप में नहीं था।

24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। चूँकि यह आरोपी नंबर 1 था जिसने मृतक को 17.12.1985 को सुबह 00.45 बजे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी पूरी होने के बाद मृतक को पुलिस लॉकअप में रखा था, यह आरोपी नंबर 1 पर था कि वह मृतक के शरीर पर लगी चोटों के बारे में बताए। उन लोगों के अलावा अन्य मृतक जिन्हें पूर्व में देखा गया था। 76. अभियुक्त नंबर 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 313 के तहत अपने बयान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है और न ही इन चोटों को समझाने के लिए बचाव में कोई सबूत पेश किया है। आरोपी नंबर 1 द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण या मृतक के शरीर पर इन चोटों पर स्पष्टीकरण के लिए आरोपी नंबर 1 की ओर से पेश किए गए किसी भी सबूत के अभाव में, इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि ये चोटें उसके शरीर पर लगी हैं। मृतक का शव आरोपी नंबर 1 द्वारा और किसी और ने नहीं।

25. आरोपी नंबर 1 के खिलाफ सिद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला यह है कि

(i) उसने मृतक को 17.12.1985 की रात को गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श.-76) के अनुसार सुबह 00.45 से 1.00 बजे के बीच गिरफ्तार किया था,

(ii) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीडब्लू-13 द्वारा देखी गई चोटें गिरफ्तारी पंचनामे (प्रदर्श 76) में दर्ज चोटों से अलग और अधिक गंभीर हैं और

(iii) मृतक की हिरासत के समय के बीच किसी और के पास मृतक की हिरासत नहीं थी। 17.12.1985 को प्रातः 0.45 बजे से 17.12.1985 को प्रातः 7.00 बजे तक गिरफ्तारी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र परिकल्पना यह है कि यह आरोपी नंबर 1 है जो मृतक के शरीर पर उसकी मृत्यु के समय मिली चोटों के लिए जिम्मेदार है।

26. पीडब्लू-13 ने साक्ष्य में आगे कहा है कि मृतक के शरीर पर आंतरिक परीक्षण करने पर उसने निम्नलिखित चोटें देखीं:

1. दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर हेमेटोमा गोलाकार 2" व्यास का।

2. बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर हेमेटोमा गोलाकार 2" व्यास का।

3. मस्तिष्क का आवरण सामान्य, मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम।

4. दाहिनी ओर 7 वीं, 8 वीं पसलियों में फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी से 2 इंच पीछे। फ्यूरा सामान्य ट्रैक्स भोजन के कण, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा संकुचित था। फील कार्डियन सामान्य था। सुना है मेरा वजन 400 ग्राम है, फेफड़े की वाहिकाएं खाली हैं।

5. पेट की दीवारें सामान्य थीं, पिछली सतह पर दरार को छोड़कर पेरिटोनजर्न सामान्य था। कैविटी- करीब 2 लीटर खून, बकल कैविटी सभी

दांत मौजूद थे। ओइसोफैब्स में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। पेट और इसकी सामग्री: लगभग आधा वाटी भूरे रंग का तरल पदार्थ जिसमें चावल छोटी आंत और इसकी सामग्री: अर्ध पचा हुआ भोजन, बड़ी इंस्टाटिन और इसकी सामग्री: मल पदार्थ। लिवर: Wt. 1.5, लीवर के दाहिने लोब की पिछली सतह पर घाव, 2"x1"

पीडब्लू-13 ने साक्ष्य में आगे कहा है कि उनकी राय में मौत का कारण जिगर में चोट के कारण रक्तस्राव के कारण सदमा, कई चोटों के साथ पसलियों के फ्रैक्चर के कारण था। पीडब्लू-20, सीपीआर अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने पीडब्लू-13 के साथ मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम भी किया था, ने अदालत के समक्ष गवाही दी है कि मृतक की मृत्यु मुख्य रूप से पसलियों के टूटने के कारण हुई थी। मृतक और पसलियों में पेरिटोनियम, डायाफ्राम और फुस्फुस के माध्यम से प्रवेश किया और यकृत को प्रभावित किया। पीडब्लू-20 ने यह भी बताया है कि चोटें पोस्टमार्टम से 12 से 15 घंटे पहले के बीच लगी थीं। पोस्टमार्टम शाम 5.45 बजे से 7.45 बजे के बीच किया गया और 5.45 बजे से 15 घंटे बाद 16.12.1985 की मध्यरात्रि के आसपास हुआ। इस प्रकार यह उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है कि मृतक के शरीर पर आई चोटें और विशेष रूप से पसलियों की चोटें मृतक की मृत्यु का कारण थीं और आरोपी नंबर 1 मृतक पर इन चोटों के लिए जिम्मेदार था।

27. हालाँकि, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि आरोपी नंबर 2 और 3 मृतक को चोट पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार थे जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। जैसा कि हमने पाया है, मृतक की गिरफ्तारी के समय और शाहपुरी पुलिस स्टेशन में जब गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श 76) तैयार किया गया था, तब आरोपी नंबर 2 और 3 मौजूद थे और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि आरोपी नंबर 2 और 3 ने मृतक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था। पीडब्लू-23 ने कहा है कि 17.12.1985 को सुबह 00.30 से 1.00 बजे के बीच गोकुल होटल के पास स्कूटर की लाइट बंद हो गई और आरोपी नंबर 1 ने उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और वह पुलिस स्टेशन गया और कुछ समय जुर्माने की रसीदें बनाने के लिए आवश्यक था जिसे उसने भुगतान किया और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया और अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया कि जीप के चले जाने के बाद, साधारण पोशाक में दो पुलिसकर्मी भी उससे पहले पुलिस स्टेशन से चले गए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोल्हापुर, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत मृतक की मौत की जांच की, ने कहा है कि जांच के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न पुलिस कांस्टेबलों के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी नंबर 2 और 3 ने दिनांक 17.12.1985 को लगभग 1.00 बजे मृतक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन छोड़ दिया गया। साहूपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पीडब्लू-29 ने यह भी

कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि आरोपी नंबर 2 और 3 साइकिल पर पुलिस स्टेशन से निकले थे और 17.12.1985 की सुबह 7.20 बजे तक वे पुलिस स्टेशन नहीं लौटे थे। शाहूपुरी पुलिस स्टेशन की पुलिस स्टेशन डायरी (प्रदर्श 113) में प्रविष्टि में कहा गया है कि पन्हाले (अभियुक्त संख्या 1) ने व्यक्तिगत रूप से मृतक को लॉक-अप में रखा था और उक्त प्रविष्टि में अभियुक्त संख्या 2 और 3 की हवालात में उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जहां मृतक को रखा गया था। मुकदमे में यह सबूत होने के कारण, उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि मृतक की मृत्यु आरोपी नंबर 2 और 3 की हिरासत में हुई थी। हमारी राय है कि आरोपी नंबर 2 और 3 की दोषसिद्धि रद्द की जानी चाहिए।

28. एकमात्र अन्य प्रश्न जो हमें तय करना है वह अपराध की प्रकृति के बारे में है जो आरोपी नंबर 1 ने किया है। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह नहीं दिखाते हैं कि आरोपी नंबर 1 का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था या उसका इरादा शारीरिक चोट पहुंचाने का था क्योंकि वह जानता था कि इससे मृतक की मौत होने की संभावना है या उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह भी स्थापित नहीं करते हैं कि वह जानता था कि मृतक के शरीर पर आई चोटों से उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना है या उसकी मृत्यु होने की संभावना

है। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित हत्या के अपराध की सामग्री आरोपी नंबर 1 के खिलाफ स्थापित नहीं की गई है। हमारी सुविचारित राय में, आरोपी नंबर 1 भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी नंबर 1 का मृतक की मृत्यु का कारण बनने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था जिससे मृतक की मृत्यु होने की संभावना हो अत आरोपी नंबर 1 को सात साल के कठोर कारावास की सजा और 3,000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाना और अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा से दण्डित किया जाना पर्याप्त होगा।

29. इसलिए, हम अभियुक्त संख्या 2 और 3 की आपराधिक अपील संख्या 1004 ऑफ 2007 की और 1005 ऑफ 2007 की अनुमति देते हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 218, 342 और 302 के तहत उनकी दोषसिद्धि को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि आरोपी नंबर 2 और 3 के जमानत मुचलके जारी होने पर बरी कर दिया जाये।

30. आरोपी नंबर 1 द्वारा दायर आपराधिक अपील नंबर 1067 ऑफ 2007 में, हमने आईपीसी की धारा 193, 218 और 342 के तहत आरोपी नंबर 1 की सजा को रद्द कर दिया, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 302 के अपराध के बजाय, आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध का दोषी

ठहराते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास और उस पर 3,000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माने पर छह माह के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतेगा। आरोपी नंबर 1 जो जमानत पर है, उसे सजा की शेष अवधि काटने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। आपराधिक अपील संख्या 1067 ऑफ 2007 निस्तारित की जाती है ।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीले ख़ारिज की गई.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अविनाश चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।